(e) when the Central Board of Secondary Education has not declared any students as "Pass" or "Fail" how have they "detained" number of students?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) 47012 candidates appeared at the Delhi Secondary School Examination, 1977.

(b) and (c). As per the present criteria, students securing 30 per cent and above marks in all the subjects are eligible for admission in one or the other course to Class XI. 29594 candidates fall in this category. The students getting less than 30 per cent marks in one or two subjects are eligible for Compartmental Examination to be held on 10th August, 1977. 9669 candidates are eligible for one subject Compartment and 5765 for two subjects Compartmental Examination. These candidates on securing 30 per cent or more marks in the Compartmental Examination in one or two subjects, as the case may be, will become eligible for admission to Class XI. As such out of 47012 candidates who appeared at the 1977 Examination only 2984 candidates are not eligible for admission to Class XI.

(d) No, Sir.

(e) The candidates were not declared pass and fail but the criteria was laid down only to have a uniform policy of minimum standard for admission.

भूमि उपयोग बोर्ड

5492. **श्री मीठालाल पटेल:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना करने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्य उक्त बोर्डों की स्थापना के लिए सहमत हो गये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक 22 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना कर चुके हैं । (विवरण संलग्न है) :

इनके अलावा —

(1) गुजरात सरकार ने मृदा तथा जल प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना की है जो उनके कथनानुसार राज्य में भूमि उपयोग बोर्ड का कार्य करेगा ।

(2) आंध्र प्रदेश की सरकार "आंध्र प्रदेश भूमि सुधार" योजना सम्बंधी विधेयक की तैयारी के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिसमें "राज्य स्तरीय बोर्ड" की स्थापना करने की व्यवस्था है जो भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सिद्धान्तों के आधार पर भूमि उपयोग सम्बन्धी मामलों को भी निपटाएगा ।

(3) उड़ीसा और राजस्थान की सरकारें भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

विवरण

राज्य / संघराज्य क्षेत्र जहां भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं —

1. हिमाचल प्रदेश
2. महाराष्ट्र
3. उत्तर प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. हरियाणा
6. तमिलनाडु

7. मणिपुर
8. केरल
9. बिहार
10. कर्नाटक
11. असम
12. मेघालय
13. प० बंगाल
14. नागालैण्ड
15. पंजाब
16. त्रिपुरा
17. जम्मू व काश्मीर
18. गोवा, दमन तथा दीव
19. अरुणाचल प्रदेश
20. दिल्ली
21. पांडिचेरी
22. मिजोरम

गुजरात में छात्रों को छात्रवृत्तियां

5493. **श्री चौधरी मोती भाई आर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त रिहायशी माध्यमिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1975–76 और 1976–77 में छात्रवृत्तियां मंजूर की गई और उनमें कितनों को वस्तुतः छात्रवृत्तियां मिलीं ;

(ख) गुजरात में मान्यता प्राप्त रिहायशी माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने स्कूलों में शिक्षा का माध्यम गुजराती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में गुजराती माध्यम के स्कूलों को भी मान्यता देने का है क्योंकि इस प्रकार के स्कूलों के न होने के कारण छात्रवृत्ति धारियों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित होना पड़ता है ;

(घ) क्या गुजराती माध्यम के अच्छे स्कूलों को भी मान्यता नहीं दी जा रही है; और

(ङ) क्या छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को गुजराती माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों में तब तक पढ़ने की अनुमति दी जाएगी जब तक वे स्कूल मान्यता नहीं प्राप्त कर लेते ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) अनुमोदित रिहायशी माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अधीन 1975–76 के दौरान गुजरात में छात्रों को 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिसमें से 18 ने लाभ उठाया। दो छात्रवृत्तियों को रद्द कर दिया गया क्योंकि चुने हुए विद्यार्थियों के माता पिता की आय योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय से अधिक थी। 1976–77 में 10 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं और सभी ने उनका उपयोग किया।

(ख) तीन। गुजराती माध्यम वाला कोई नहीं है।

(ग) जी हां।

मंत्रालय ने गुजरात सरकार से कुछ अच्छे गुजराती माध्यम के रिहायशी स्कूलों की सिफारिश करने का अनुरोध किया है और चार ऐसे स्कूलों मे अनुमोदित स्कूलों की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से, कुछ आवश्यक सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) केवल उन्हीं स्कूलों का अनुमोदन किया जाता है, जो योजना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किसी भी अच्छी